MR. SPEAKER: Shri Kanwar Lal Gupta.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED TALKS BETWEEN INDIAN AND PAKISTAN HIGH COMMISSION RE. RESUMPTION OF TRADE BETWEEN INDIA AND PAKISTAN AND OTHER MATTERS

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार को पुनः आरम्भ करने के बारे में दोनों देशों के उच्चायुक्तों और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री की कथित वार्ता और कलकत्ते में हुई बैठक में दिये गये महासंघ (कन्फैडरेशन) के सुझाव ।"

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): Sir, presumably the Hon'ble Member is referring to the newspaper reports that the Pakistan High Commissioner, while on a visit to Calcutta, called on the Chief Minister of West Bengal and that during this meeting the question of resumption of trade between India and Pakistan was also discussed. The call by the High Commissioner was a courtesy call in which the question of resumption of trade between the two countries also came up in a general way. The West Bengal Government leaders mentioned to the High Commissioner that they would welcome normalisation of relations between the two countries but it was a matter under the purview of the Central Government.

2. The Government's views on the resumption of trade between India and Pakistan are a well known. We removed the ban on trade with Pakistan as far back as May, 1966. The Government of Pakistan has not reciprocated and trade with India continues to be banned in Pakistan. We have, on a number of occasions, raised through diplomatic channels the desirability of resuming trade between the two countries but the Government of Pakistan have not responded.

3. So far as the statements made at a meeting in Calcutta on April 26 in favour of an Indo-Pak Confederation are concerned, it is an entirely different subject from the one I have just dealt with. We have seen newspaper reports of the Calcutta meeting at which some speakers, including some Members of Parliament, spoke in favour of a Confederation of India and Pakistan in the larger interest of peace and progress. These Speakers were expressing th ir own views and did not represent the views of the Government. While it is the policy of the Government of India to improve and develop co-operative relations with Pakistan we are not seeking confederation between the two countries.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि विदेशी राजदूत हमारे देश के नेताओं व राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के पास कर्टसी कौल भी करते हैं परन्तु इसे महज कर्टसी कौल करना यह ओवर सिम्प्लीफिकेशन होगा । अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार की बातचीत करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ व्यापार नहीं करता है । यह व्यापार, फरक्का बराज और बाऊन्डरी डिस्प्यूट यह जो तीन बातें कही गई हैं तो यह तीनों विषय केन्द्रीय सरकार के हैं । पाकिस्तान की सरकार केन्द्र के साथ व्यापार के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती है लेकिन बंगाल के मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत करना चाहती है और उसके बाद भी मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह कर्टसी कौल है । यह ओवर सिम्प्लीफिकेशन है और यह बहुत चिन्ता की बात है ।

MR. SPEAKER: That is your view.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: That is my view.

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो यह बातचीत की गई है और खास तौर से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने डिप्लोमैटिक कन्वैंशन को तोड़ दिया है, एक प्रोपराइटी को भी खत्म कर दिया तो यह बहुत चिन्ता का विषय है । यह बहुत मिस्चीवियस मूव है ।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं और वह आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, आपने अपनी पालिसी भी बताई, मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नार्मल रिलेशन होना चाहिए लेकिन यह जो डील है, पीसमील डील नहीं चाहिए लेकिन जहां पाकिस्तान को लाभ हो···

MR. SPEAKER: Come to the question now; what is the clarification you want?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने पालिसी की बात कही कि डील पीसमील नहीं होना चाहिए तो क्या पाकिस्तान ताशकन्द एग्रीमेंट को पूरी तरह निभाता है तब उसके साथ नार्मलाइज़ करें अन्यथा नहीं ? यह हमारी किश्तियां, जहाज बेच दें, भुट्टो आपके काम पकड़े खुल्लमखुल्ला और आप उसके आगे हाथ जोड़ा करें तो यह ठीक नहीं है। मेरा पहला सवाल यह है कि यह इन्वीशिएटिव किसका था क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है और आल इंडिया रेडियो के मुताबिक इन्वीशिएटिव की जो बातचीत हुई थी वह वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हुई और कुछ अखबारों में दूसरी रिपोर्ट भी है ? स्वयं जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इन्वीशिएटिव लिया तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बातचीत में इन्वीशिएटिव किसने लिया ?

दूसरी चीज यह कि क्या आपने पाकिस्तान हाई कमिश्नर को प्रोटैक्ट किया या नहीं किया ? आपने उनसे बातें कीं, एक घंटे तक बातचीत हुई है। आप हमसे बातचीत नहीं करते हैं। केन्द्र का विषय है तो क्या आपने इस तरह का प्रोटैस्ट पाकिस्तान हाई कमिश्नर को किया है ? कल को विदेशी हाई कमिश्नर, यह डिप्लोमेट्स हर एक राज्यों के मुख्य मंत्रियों आदि के पास जायेंगे, अलग-अलग बात करेंगे और एक अलग परम्परा इस तरह कायम होगी। क्या पाकिस्तान यह समझता है कि बंगाल भारत के बाहर है ? क्या बंगाल कोई अलग देश है ? आखिर बंगाल भारत का एक हिस्सा है। आपको इनको समझा देना चाहिए। क्या सरकार हर एक डिप्लोमेट को साफ तौर पर बता सकेगी कि जो केन्द्र के विषय हैं उनके बारे में विदेश के लोग केन्द्र के साथ बातचीत करें, अलग-अलग प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों आदि से बात न करें।

आखिर में मेरा कहना यह है कि एक जो उसकी बैकग्राउन्ड है वह भी देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान का चीन के साथ सम्बन्ध है। पाकिस्तान कहता है कि हिन्दुस्तान ही हमारा एक दुश्मन है और पाकिस्तान को हथियार मिलते हैं चीन से बंगाल में ज्योति बसु साहब कहते हैं कि यहां पर युनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट है यह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है लेकिन यह वैसी ही बात है जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में चेकोस्लावाकिया देश वालों की हकूमत है···

MR. SPEAKER: I will have to stop you. Kindly excuse me.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Please give me only two minutes.

MR. SPEAKER: You put only a question,

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आज बंगाल सरकार सही मायनों में कम्युनिस्ट सरकार है वरचुएली वह कम्युनिस्ट सरकार है और उनकी सिम्पैथी भी चीन के साथ है। जो पाकिस्तान में मौलाना भाशानी हैं या पाकिस्तान की जो सरकार है उनकी चीन के साथ सिम्पैथी है तो कहीं यह तीनों का गठजोड़ न हो जाय क्योंकि जब अजय मुकर्जी ने इस्तीफा दिया था, पिछली युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट हटी थी उस समय भी उन्होंने यह कहा था···

MR. SPEAKER: That is irrelavant. A question can be put. Can the Ambassador go straight to the State Government and talk with them on policy matters?

SHRI DINESH SINGH: For having simplified the question to which an answer can be given by me without any hesitation...

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेहरबानी करके खत्म कर लेने दिया जाय ।

मेरा सवाल यह है कि यह तीनों की कांस्परेसी न हो और देश को नुकसान न हो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या उनकी गतिविधियों पर एक क्लोज आई रख रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक माननीय सदस्य का यह सवाल है कि क्या जो विदेशी राजदूत या उनके अन्य रिप्रेजेन्टेटिव यहां पर हैं वे हमारे राज्यों की सरकारों के साथ बात कर सकते हैं, मैं साफ बतला देना चाहता हूं कि वह बात नहीं कर सकते हैं। चाहे वह मसला केन्द्रीय सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, किसी मसले पर वह सीधी बात नहीं कर सकते हैं, वह हमारे जरिये, केन्द्रीय सरकार के जरिये ही बात कर सकते हैं, और इसके बारे में हमको कोई शक नहीं है कि वहां ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसके बारे में हम ऐतराज कर सकें। मैंने अपने वक्तव्य में साफ कहा था कि वहां पर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसने खुद कहा कि वह चाहते हैं कि हमारे उनके सम्बन्ध अच्छे हों लेकिन इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से बातें करनी पड़ेंगी। इसमें कोई गलत या प्रोप्राइटी के खिलाफ बात हुई है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। मेरी खुद वहां के मंत्री महोदय से बात हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि कोई खास चर्चा वेस्ट बंगाल की सरकार और पाकिस्तान हाई कमिश्नर के बीच किसी बात को तय करने के लिए हुई है। वह कर्टसी काल के लिए गये थे, जिससे कई बातें उठीं और आम तौर से उन पर बात हुई।

जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि कौन-कौन साथ हो रहा है और उसका क्या होगा, तो वह यह क्यों समझते हैं कि सरकार बैठी कुछ नहीं करती है, सब-कुछ माननीय सदस्य ही सोचते हैं। हमको भी सब कुछ देखना पड़ता है और हम उनसे ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। लेकिन जब कोई खास बात हो तो मैं उसका जवाब दूं। एक आम सवाल है कि किसकी सिम्पैथी किसके साथ है, मैं क्या जानूं कि किसकी सिम्पैथी दिल में किसके साथ है। लेकिन जाहिरा तौर पर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके लिए हम उन पर ऐतराज कर सकें।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने इनिशिएटिव के बारे में सवाल किया था कि इनिशिएटिव किसने लिया, दूसरी बात यह कि आपने कहा कि पाकिस्तान सीधे बात नहीं कर सकता और उसने सीधी बात की। तो क्या आपने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है ? आपने इसका जवाब नहीं दिया।

श्री दिनेश सिंह : मैंने साफ कहा कि उन्होंने सीधी बात नहीं की। मैं किस तरह से कहूं ? जब लोग मिलते हैं तब कोई बात तो करनी ही होगी। कोई मौसम की बात करने थोड़े ही कलकत्ता गये थे। जाहिर है कि वहां के मिनिस्टर भी राज्य की सरकार में जिम्मेदार जगह पर हैं और जो वहां के मसले हैं उनके बारे में सरसरी निगाह से बात उनमें हुई है। और कोई बात नहीं हुई। उन्होंने भी मुझसे कहा और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भी मुझसे कहा कि उनका बात करने का कोई इरादा नहीं था, और न इस तरह से बात चीत की गई।

श्री कंवर लाल गुप्त : इनिशिएटिव किसने लिया ?

श्री दिनेश सिंह : इसमें इनिशिएटिव की बात क्या हो सकती है ? कर्टसी काल के लिए हाई कमिश्नर ने हमसे इजाजत ली थी।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन्स की पुनर्स्थापना के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया उसका हमें स्वागत करना चाहिए क्योंकि बटवारे से जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई, यानी न पाकिस्तान के साथ सौहार्द स्थापित हुआ न हिन्दू मुसलमान में

[श्री देवेन सेन]

सौहार्द स्थापित हुआ। इसलिए हमको दूसरे साधन खोजने चाहिये। हम लोगों का पाकिस्तान की आम जनता से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ दोनों देशों की सरकारों के अधिकारियों के बीच में है। इसलिए ट्रेड रिलेशन्स के जो साधन हैं उनके द्वारा दोनों देशों की जनता के अन्दर फिर से रिश्तेदारी कायम होनी चाहिए। इसमें दो किस्म के फायदे हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा सौहार्द स्थापित हो सकता है, दूसरे हमारे बिज़िनेस की भी प्रगति हो सकती है। पाकिस्तान हमारा कोल चाहता है और हम पाकिस्तान का पाट चाहते हैं। पाट हमको दूसरी जगहों से लेना पड़ता है इसलिए वह हमको मंहगा पड़ता है और कोल साउथ अफ्रीका से लेने में पाकिस्तान को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह घाटा दोनों मुल्कों को हो रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रेड रिलेशन्स ओपन करने के बारे में और कांफेड्रेशन के बारे में सरकार का क्या रुख है? कांफेड्रेशन हमारी पार्टी का सिद्धान्त तय हो गया है क्योंकि इसी तरह से सौहार्द कायम हो सकता है दोनों मुल्कों में। मैं चाहता हूं कि महासंघ कायम हो। हम चाहते हैं कि हिन्दू उन लोगों के पीरों के प्रति श्रद्धा रक्खें और वह लोग हमारे नेताओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। हम चाहते हैं कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ें। और इसकी शुरुआत हो ईस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान के आदमी वेस्ट बंगाल के आदमियों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या रुख है और ट्रेड रिलेशन्स की पुनर्स्थापना करने के बारे में उनका क्या रुख है?

श्री विनेश सिंह : मैंने अभी कहा कि हमने अपनी तरफ से पाकिस्तान से तिजारत के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं लगा रक्खी हैं। रोक पाकिस्तान की तरफ से है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वह रोक हटायें, और दोनों देशों के बीच में तिजारत बढ़े।

जहां तक माननीय सदस्य ने महासंघ के बारे में कहा, हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि दोनों देशों के बीच में महासंघ हो, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि दोनों मिल-जुलकर रहें और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों। यह भी मैं साफ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जनता के प्रति हमारे कोई बुरे खयालात नहीं हैं, हमारे मैत्रीपूर्ण खयालात हैं और हम चाहते हैं कि उनसे दोस्ती और सहयोग बढ़े।

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया): क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जब विदेश मंत्री और पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर श्री आचार्य के बीच में बातचीत हुई तो क्या उस दौरान भारतीय हाई कमिश्नर ने कुछ ऐसी बातें बतलाई हैं जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर श्री सज्जाद की बातों का पुष्टीकरण करती हैं?

श्री विनेश सिंह : किस बात का पुष्टीकरण करती हैं?

श्री कामेश्वर सिंह : कालिंग अटेंशन जो है उसमें यह है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच में व्यापार के बारे में बातचीत हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में हैं, उनसे जो बातचीत आपकी हुई है उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात बतलाई है जिससे श्री सज्जाद की बातों का पुष्टीकरण होता है?

श्री विनेश सिंह : अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे हाई कमिश्नर ने मुझसे यह कहा है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर व्यापार के बारे में केन्द्रीय सरकार से बात न करके पश्चिम बंगाल की सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे हाई कमिश्नर ने हमसे ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री कामेश्वर सिंह : मंत्री महोदय ने मेरी बात का गलत मतलब लगाया है। यह तो श्री कंवर लाल गुप्त का सवाल था।

MR. SPEAKER: We cannot help it.

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : अभी श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने प्रश्न के दौरान जो यह कहा कि बंगाल की सरकार चीनपरस्त है या पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के बारे में कहा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट के जो मुख्य मंत्री हैं श्री अजय मुकर्जी, उनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अब मैं अपना प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 1966 में जो वैन हमारी तरफ से 1965 की कांफ्लिक्ट के कारण लगाया उसको आपने उठा लिया। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान पर कैसी हुई, वह सद्भावना पूर्ण हुई या नहीं ? आपने ताशकन्द घोषणा की पृष्ठभूमि में जो यह कदम उठाया था उस का असर उन पर हुआ या नहीं ?

दूसरी बात यह कि क्या यह सच नहीं है कि रूस और अमरीका पाकिस्तान को हमेशा से शस्त्रास्त्र से लैस करते रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के सद्भावपूर्ण कदमों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह हमेशा 1965 की कांफ्लिक्ट के बदले के लिए तैयार रहते हैं ?

श्री विनेश सिंह : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि हमको किसी भी विशेष व्यक्ति पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए जिससे कुछ ऐसी झलक निकलती हो कि वह देश के हित की बात नहीं सोचते हैं। बंगाल की सरकार एक भारतीय सरकार बनी है और हम वहां के किसी भी व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहना चाहेंगे कि वह देश के हित की बात नहीं सोचते हैं।

जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है कि हमारी तरफ से तिजारत खोल देने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा है, मैं समझता हूं कि वहां की जनता ने इसको महसूस किया होगा कि भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है पाकिस्तान की जनता से।

जहां तक पाकिस्तान सरकार का सवाल है उसकी तरफ से अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमको यह लगे कि वह भी ताशकंद घोषणा के अनुसार हमारे सम्बन्ध अच्छे करना चाहती है, शांतिपूर्ण ढंग से मामलों को तय करना चाहती है।

जहां तक फौजी सामान देने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। पाकिस्तान को बड़ी तादाद में फौजी सामान देने का यह जरूर मतलब निकलता है कि शांतिपूर्ण ढंग से सुलह न करने के लिए उसको एक मदद मिलती है।

12.21 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW BY GOVERNMENT ON THE WORKING OF URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED, AND ANNUAL REPORT

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATAPATHY): On behalf of Shrimati Indira Gandhi,

I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1656:—

(1) Review by the Government on the working of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, Bihar, for the period from 4th October, 1967, to 31st March, 1968.

(2) Annual Report of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, Bihar, for the period from 4th October, 1967, to 31st March, 1968, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See.* No. LT—959/69.]

ANNUAL REPORTS OF GOA SHIPYARD LIMITED, GARDEN REACH WORKSHOPS LIMITED, BHARAT EARTH MOVERS LIMITED, PRAGA TOOLS LIMITED, AND MAZAGON DOCK LIMITED

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.R.